

प्रेषक,

डॉ० उमाकान्त पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक : 10 जून, 2016

विषय :- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थापित 03 गैस आधारित परियोजनाओं से उत्पादित 856 मे०वा० में से 428 मे०वा० गैस आधारित विद्युत क्रय करने हेतु 02 वर्षों की अवधि के स्थान पर 25 वर्षों की अवधि के अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार की "The scheme for utilization of gas based power generation capacity for the year 2015-16 and 2016-17 (Dated 27.03.2015) के क्रम में निर्गत शासनादेश सं०-456 दि०-28-04-2015 तथा उसके उपरान्त उ०पा०का०लि० के पत्र सं०-780 दि०-16-03-2016 एवं सं०-1002 दि०-02-04-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस पत्र द्वारा उपरोक्त गैस आधारित परियोजनाओं से 25 वर्ष के Power Purchase Agreement (PPA) का प्रस्ताव दिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अधिसूचना दि०-10-09-2015 के बिन्दु सं०-83(बी) तथा 55(ए) में सुसंगत विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०-456 दि०-28-04-2015 में PSDF योजना हेतु किये जाने वाले विद्युत गैस क्रय अनुबन्ध पत्र की अवधि 02 वर्षों (Short Term) के स्थान पर 25 वर्षों (Long Term) Life of Project के लिये निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. राज्य में विद्युत मांग को पूरा करने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० द्वारा आंकलित ऊर्जा की आवश्यकता तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों के अन्तर्गत यदि उत्तराखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग ऐसा करने की अनुमति दे, तो तीनों गैस आधारित परियोजनाओं से उनकी पृथक-पृथक कुल उत्पादन क्षमता (क्रमशः मै० श्रावन्ती क्षमता 428 मेगावा०ट, मै० बीटा क्षमता 214 मेगावा०ट तथा मै० गामा क्षमता 214 मेगावा०ट) अर्थात् कुल उत्पादन क्षमता का अधिकतम 50% तक अथवा आवश्यकतानुसार जैसा भी उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अनुमन्य करे, गैस आधारित ऊर्जा का क्रय करने हेतु 02 वर्ष (Short Term) के स्थान पर Long Term अर्थात् 25 वर्षों हेतु क्रय अनुबन्ध किया जायेगा।

2. गैस आधारित ऊर्जा के क्रय के सम्बन्ध में हस्ताक्षरित किये जाने वाले अनुबन्ध पत्रों की शर्तों का विधिक/व्यवहारिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से विस्तृत परीक्षण का दायित्व उपाका०लि० का होगा।

अतः उक्त शर्तों के अतिरिक्त पूर्व शासनादेश दि०-28-04-2015 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

अतः तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

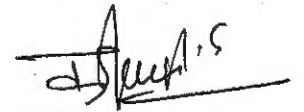
(डॉ० उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्या-444 (2)/2016-04/15/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन को उनके आदेश दि०-09-06-2016 के क्रम में सूचनार्थ।
6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
9. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
11. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
12. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
13. मै० श्रावन्ती इनर्जी प्रा० लि०, तीसरा तल, राईडर हाऊस-136, सैक्टर-44, गुड़गांव-02
14. मै० गामा इन्फ्राप्रोप प्रा० लि०, एम-3, पहला तल, अरबिन्दो मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-16
15. मै० बीटा इन्फ्राटेक प्रा० लि०, बी-4/45, सफदरजंग इन्वलेव, नई दिल्ली-29
16. प्रभारी निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
17. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,



(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव